श्री राजेश पायलट : अगर किसी ने यह हवा फैलाई है तो हम यह नहीं होने देंगे ।

श्री अमरजीत सिंह : मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि ला एंड आर्डर स्टेट्स की प्राब्लम है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1984 के रॉयट्स में कौन सी सरकार थी और किस स्टेट से रिपोर्ट की इंतजार कर रहे हैं ? दूसरा सवाल यह है कि मंत्री जी ने लोक सभा में दो दिन पहले कहा है कि जैन-बैनर्जी कमीशन जो रायट्स प्रोब कर रहा था उसकी एक्सटेंशन के लिए लीगल आसपेक्ट्स एक्जामिन कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट लो करने के लिए भी लीगल आसपेक्ट्स एक्जामिन कर रहे हैं । 9 साल हुए दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई । मुझे उनकी नीयत पर शक होता है । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं अब इन दोषियों को कब तक सजा दिलवायेंगे और कमीशन की टर्म्स को क्या आप एक्सटेंड कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट को हाउस में टेबल पर ले करेंगे या नहीं ?

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदय, मैंने, दूसरे हाउस में जब सवाल उठा था तो जवाब दिया था कि कुछ एक्शन हुआ है । लेकिन हम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाये । उनको हम बता नहीं पाये । यह हमारी कमी थी, हमारे विभाग की कमी थी । जो एक्शन हमने लिये वह भी जनता तक नहीं पहुंच पाये । मैंने आश्वासन दिया है, दूसरे हाउस में भी कहा है कि जैन-बैनर्जी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी पार्टी से सम्बन्धित हो, कहीं भी हो, चाहे किसी भी विभाग में हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी जो 1984 के रॉयट्स में इन्वाल्व हैं ।

मैंने यह भी कहा है कि अभी टाइम नहीं है लेकिन अगली बार जब सदन मिलेगा उससे पहले मैं पूरी रिपोर्ट सदन के सामने लेकर आऊंगा, कौन-कौन दोषी पाये गये हैं, किस रिपोर्ट में दोषी पाये गये हैं, सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी ये सब बातें मैं दोनों सदनों को बता कर रहूंगा । इसमें कोई चीज छिपाने की बात नहीं है । इसमें कोई नरमी नहीं बरतेंगे । माननीय सदस्य की यह भावना गलत है कि इसमें ढील बरती जायेगी । मैं बताना चाहता हूं कि हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे । यह मैंने उस सदन में भी आश्वासन दिया है ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : चेयरमैन साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कब आप इन दंगाइयों पर प्युनिटिव टेक्स लगायेंगे ? क्योंकि टेररिस्ट जब कोई आतंकवाद के माध्यम से किसी को मार देता है तो उसकी प्रोपर्टी अटैच कर ली जाती है और जब दंगाई समाज में ऐसा विषाक्त माहौल बनाकर साम्प्रदायिक दंगे कराते हैं तो उन पर प्युनिटिव टेक्स सरकार लगा रही है या नहीं लगा रही है यह मैं जानना चाहता हूं । दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि दंगे में बहुत लोग मारे जाते हैं किन्तु देखा जाता है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक हमारे भारतवासियों की कीमत मरने के बाद कहीं कम हो जाती है, कहीं बेशी हो जाती है । एक यूनिफार्म कम्पेंसेशन होना चाहिए । लेकिन कहीं 20 हजार मिलता है, कहीं 10 हजार मिलता है और कहीं एक लाख दिया जाता है । वह पर्टिकुलर कम्युनिटी के पोलिटिकल वेट के हिसाब से तोला जाता है । ऐसा नहीं करना चाहिए । दंगे में मारे गये हर भारतवासी की जो कम्पेंसेशन हो वह पूरे भारत में एक होनी चाहिए । उसके बारे में आप कब विचार करेंगे ?

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : मेघालय में 5 हजार रुपये दिये जाते हैं । जैकब साहब इस बात को जानते हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदय, यह बात सही है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, जो भी भाई और बहन कम्यूनल रायट्स में मारे जाये उसका स्टेटवाइज अलग अलग कम्पेंशसन नहीं होना चाहिए । इसी बेस पर हमने होम मिनिस्ट्री की तरफ से सारे मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि इस संबंध में एक युनिफार्म पालिसी होनी चाहिए । जो भी कम्पेंसेशन दिया जाय, किसी भी स्टेट का हो, युनिफार्म होना चाहिए । हिन्दुस्तान के हर नागरिक की जान सब के लिए बराबर है । कुछ स्टेटों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है । मैं पर्सनली इसको मोनिटर कर रहा हूं । मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सारी सरकारों को एक लाइन पर ला सकेंगे कि कम्पेंसेशन सब को एक रूप में दिया जाय । दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि प्यूनिटिव टेक्स कम्यूनल रायट्स पर लगे । सरकार की यह कोशिश है और सरकार कोशिश कर रही है कि एक बिल रिलीजन नाट मिसयूज्ड इन पोलिटिक्स, ऐसा कदम उठाया जा रहा है । एक रेपिड एक्शन फोर्स भी बनाई है और दूसरे कदम भी उठाये हैं और इसलिए उठाये हैं कि किसी न किसी रूप में जो लोग इसमें इंवोल्व होते हैं उन पर सख्त कार्यवाही हो और उनको सख्ती नजर भी आये कि सरकार उनको आसानी से नहीं छोड़ेगी । सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी । इस वक्त यही कदम सरकार की तरफ से उठाया जा सकता है ।

Changing the length of metre gauge railway lines into broad gauge

*302 SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total length of metre gauge railway lines proposed to be changed into broad gauge lines during the Eighth Five Year Plan period; and

(b) the details of metre gauge railway lines to be changed into broad gauge lines in the State of Punjab during the said plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) About 6,000 kms.

(b) Punjab had only 102 kms of MG section

before start of VIII Plan out of which 8(1 kms. section from Kotkapura to Fazilka has already been converted into BG during 1992-93. The remaining 22 kms. on Bhatinda-Sirsa section is scheduled for conversion during 1993-94. Thus. no MG. line would be left in Punjab after March. 1994.

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : सर, मेरी दर्ख्वास्त मिनिस्टर साहब से यह है कि मैंने पहले भी बोला है और अब भी क्वेश्चन किया है कि लुधियाना से एक ट्रेन चलती है लुधियाना टू फिरोजपुर और लुधियाना टू धूरी, शाहपुर मंसीया जो बहुत मीटरगेज है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

SHRI K. C. LENKA: Sir, the lines which are being selected and given priority for conversion will provide the alternative passage to the existing BG trunk lines. So, the Railways have selected 15 lines which would be converted during the Eighth Five Year Plan and it is about 6.0(1(1 kms. So, in Punjab, the Kotkapura-Fazilka line is 80 kms. and the 22 km. Bhatinda-Sirsa is a part of the line Rewari-Hissar-Bhatinda which goes through Haryana and Punjab and this line has been selected and the Punjab portion of it will be completed this year, the 22 km. section.

MR. CHAIRMAN: You put your second supplementary.

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : सर, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो हमारे लुधियाना की रेलवे लाइन है, नई लाइन चण्डीगढ़ के लिए है उसका आप क्या कर रहे हैं ?

SHRI K. C. LENKA: This is about the programme of conversion of MG lines into BG lines and the lines which have been selected fur conversion on priority I have already mentioned. With regard to Ludhiana-Firozpur. it is already a BG line and there is no question of any conversion.

SHRI MOHINDER SINGH KALYAN: About Ludhiana-Chandigarh ?

MR CHAIRMAN: Shri Ram Deo Bhandari.

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : लुधियाना टू चंडीगढ़ के लिये क्यों नहीं बना पाये ?...(व्यवधान)...

MR CHAIRMAN: Mr. Kalyan, please.

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : 1953 में इसका सर्वे हुआ लेकिन आज 1993 में भी ....(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Your turn is over. You cannot make a speech. Will you sit down ?

श्री रामदेव भंडारी : महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में 6 हजार किलोमीटर छोटी लाइन से बड़ी लाइन बनाने की योजना है। मैं सिर्फ 37.42 किलोमीटर की बात कर रहा हूं। महोदय, समस्तीपुर से दरभंगा तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना पर 1984 से काम शुरू हुआ और नवीनतम लागत, जो सरकारी आंकड़े हैं, उनके अनुसार 28 करोड़ 27 लाख है। 1992-93 के अंत तक इस पर सिर्फ अनुमानित पांच लाख रुपये खर्च किये गये और 1993-94 में इसके लिये एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। महोदय, इस लाइन का संबंध इंडो-नेपाल बार्डर से है और हम सभी जानते हैं कि उस क्षेत्र में बराबर बड़ी नदियों की वजह से बाढ़ और भूकम्प भी आते रहते हैं। इस प्रकार यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या एक करोड़ रुपया देकर या पांच लाख रुपया देकर सिर्फ भरोसा दिला रहे हैं कि हम इस लाइन को बनाने जा रहे हैं। यदि सचमुच में वे चाहते हैं, उनकी नीयत है कि इस लाइन को बनाया जाय तो वह स्पष्ट जवाब दें कि कब तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना है ? इसका कृपया स्पष्ट जवाब दें अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ?

SHRI K. C. LENKA: Sir, the Railways are facing a financial constraint, and the budgetary support has been decreased year by year. So. Sir, this is the money which has been allotted for this particular line, and the completion of the line as soon as possible depends upon the availability of funds.

श्री रामदेव भंडारी : 28 करोड़ कुछ भी नहीं है। सिर्फ मंशा चाहिये, नीयत होनी चाहिये। 28 करोड़ रुपये तो कुछ भी नहीं है।

MR. CHAIRMAN : Anything more?

SHRI K. C. LENKA: Sir, this line does not relate to the question. The question is about the programme of conversion in Punjab. However, this line has been included for conversion by 1994-95.

AN HON. MEMBER: Why not ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): I am sorry, Sir. The question is about gauge conversion and also particularly relating to the State of Punjab. And, therefore, what is relevant to the question is already being answered. If the hon. Member wants any other information, he should put a separate question.

MR CHAIRMAN: Shri Kailash Narain Sarang.

श्री कैलाश नारायण सारंग : धन्यवाद सभापति महोदय। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया।

सभापति महोदय, रेलवे विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 6 हजार किलोमीटर रेलवे लाइन गेज परिवर्तन का लक्ष्य रखा है जिसमें 1993-94 के लिये 16 सौ किलोमीटर परिवर्तन का लक्ष्य है, जब कि इस बारे में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष 100 किलोमीटर का लक्ष्य रखा था। इससे एक बात स्पष्ट हुई कि सरकार ने यह समझ लिया है कि देश के आर्थिक विकास में छोटी रेल लाइनें उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पा रहीं हैं जितना कि बड़ी लाइनें दे रही हैं। सभापति महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश की किन किन रेलवे लाइनों को मीटर गेज से ब्राड गेज में परिवर्तित किया जा रहा है? 1993-94 में नीमच-रतलाम लाइन को शामिल किया गया है लेकिन काफी समय से मांग चल रही है। गोंदिया-जबलपुर-अजमेर-खंडवा लाइनों को गेज परिवर्तन के लिये, जिसके बारे में तत्कालीन रेलवे मंत्री ने आश्वासन भी दिया है। तो क्या इन लाइनों को आठवीं योजना में शामिल किया गया है या नहीं? कृपया यह बताने का कष्ट करें।

SHRI K. C. LENKA: Is it M. P. or U. P.?

AN HON. MEMBER: M. P. *(Interruptions)*

SHRI K. C. LENKA: Sir, in Madhya Pradesh, the existing length of the metregauge lines is 497.80 Kms. We have included in the Action plan a total of 619 kms. for conversion to broad gauge during the 8th Five-Year Plan.

श्री कैलाश नारायण सारंग : सभापति महोदय, मैंने स्पेसेफिक प्रश्न पूछा था जबलपुर, गोंदिया, रतलाम और अजमेर के बारे में कि इस 619 किलोमीटर में कौन कौन-सी लाइनें हैं? बहुत समय से यह मांग चली आ रही है, इनमें कौन कौन-सी है, यह मुझे बताया जाए। यह मेरी प्रार्थना है (व्यवधान) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को भी नहीं समझ पा रहे है (व्यवधान)

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: As I said before, the main question relates to the total quantum of broad gauge programme that we have taken up under the unigauge policy. The second part of the question relates to Punjab. So the information available with us at the moment relates to Punjab. With regard to other States, hon. Members have to ask a separate question.

श्री कैलाश नारायण सारंग : सभापति महोदय, एक सेकेंड का प्रश्न है। ऐसे सारे प्रश्नों पर अनेक बार अलग अलग लोग अलग अलग स्टेट्स के बारे में पूछते हैं। यह कोई क्राइटेरिया यहां नहीं रहा है। यह सब हमारे सीनियर मेम्बर इस बात को जानते हैं। यह अनावश्यक इस बात को आप कह रहे है। आप यह सूचना दो चार दिन बाद लिख कर के भेज दीजिये (व्यवधान)

श्री सी॰ के॰ ज़ाफर शरीफ : देखिये सवाल यह नहीं है, अगर उस नेचर का होता तो उसी प्रकार से हम तैयार हो कर आते। आप मेन क्वेश्चन देख लीजिये (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : सभापति महोदय, मीटर गेज को ब्राड गेज में कनवर्ट करने की बात चल रही है लेकिन मैं यह पूछता हूं कि मीटर गेज को ब्राड गेज में कनवर्ट करने के बजाय जहां पर अभी तक रेल नहीं पहुंची है वहां पर रेल पहुंचाने के लिए क्या कभी मंत्रालय ने सोचा है। बहुत देर से जो लोग चीकल रहे और जो लोग आगे बढ़ते रहे, उन लोगों ने अपने अपने एरियाज़ में मीटर गेज, ब्राड गेज लाइने बिछवा ली। जो इलाके पिछड़े हुए है जहां न मीटर गेज है, न ब्राड गेज और न नेरो गेज है, उन इलाकों में मीटर गेज या ब्राड गेज लाइने बिछाने की बात क्यों नहीं सोची जाती है? दूसरे इलाको में चेंज करने की क्यों सोची जाती है? ऐसे एरियाज़ में जहां रेल लाइन नहीं है वहां की बात क्यों नहीं सोचते हैं? जहां लोगों के पास आने जाने के साधन नहीं है, महाराष्ट्र में बहुत से एरियाज़ है जहां अभी तक रेल की सुविधा नहीं है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और ईस्ट में (व्यवधान)

श्री सुशील कुमार सम्भाजीराव शिन्दे : महाराष्ट्र में बहुत दिक्कत है (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : बहुत दिक्कत है, मैं भी यही कहता हूं, महाराष्ट्र में बहुत से एरियाज़ है जो रिमोट है, जहां लाइन नहीं है, कर्नाटक में भी है, सारे देश में ऐसे रिमोट एरियाज़ है इसलिए मैं चाहूंगा कि चेंज करने के बजाय नयी लाइने बिछाई जानी चाहिये। पंजाब में भी कुछ एरियाज़ है जैसे पठानकोट से जोगिन्दर नगर अगर यह कहे कि उसको ब्राड गेज करना है, जैसे बटाला से ब्यास, चंडीगढ़ से लुधियाना, ऐसे कुछ रिमोट एरियाज़ है जहां लाइने नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वहां नयी लाइने बिछाने के बारे में सोच रहे है या जो डवलपड एरियाज़ है उन्हीं के बारे में ही सोच रहे है और जो पिछड़े है उनके बारे में नहीं सोच रहे है?

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF : I am sorry, in spite of the fact that it is almost two years now that we have taken up the unigauge policy and have taken up 6000 kms route and the work is going on throughout the length and breadth of the country, the policy of unigauge is not being understood properly by the Members. I am very happy that the hon. Member has put this question. The multigauge policy has not benefited our country. It is the British legacy. Wherever they wanted, they laid the narrow gauge or metre gauge, and the rulers of different states contributed towards it in order to have some kind of a railway line. But all these lines, whether they are metre gauge or norrow gauge, are not economical. They are all losing. The

metre gauge is subsidised by the broad gauge. The areas that are served by the metre gauge and the narrow gauge. .

SHRI VIREN J. SHAH: The question was different

SHRI C. K JAFFAR SHARIEF : The areas that are served by the metre gauge and the narrow gauge are, in no way, being developed. The hon. Member was asking as to why we are not looking at other areas. New line is another area. We have not abandoned it. Wherever there is a scope, we take it up. When there is a demand for some new line, we conduct a survey, a traffic survey. If the area is developed and if there are going to be assured returns, certainly, within the constraint of resources, we go to the Planning Commission for clearance. If the Planning Commission clears it, we take it up. Therefore, we have not given up laying lines in new areas based on the development of the area and on the factor of assured returns. It also depends on the clearance by the Planning Commission and Resource Availability. Again, wherever doubling is going on, that programme is also continuing.

Sir, we have taken up this gauge conversion programme because under the multigauge system, there is a serious bottleneck in traffic. That is why we decided on this unigauge policy. This, in no way, conflicts with what the hon. Member has in mind.

SHRI DAYANAND SAHAY: Mr. Chairman, Sir, the question of Mr. Mann has not been properly answered. I want to make it more clear. What is the budget, what is the allocation for conversion ? What is the annual allocation for new lines? My hon. friend was asking whether you want to go on improving the areas which are already improved, or, whether you are going to take up those areas where no railway lines have been laid so far. If the hon. Minister says that they are proportionately allocating money for the various programmes, that the Railways are allocating so much money for conversion and so much money for new lines, Members would be more satisfied. The hon. Minister may kindly answer this question.

SHRI K. C. LENKA: Sir, during the Eighth Five-Year Plan, we have programmed to convert about 6,000 kms. of metre gauge into broad gauge. For this, the estimated cost is Rs. 3,900 crores. Now, out of the total outlay of Rs. 27,202 crores in the Railway Budget, allocations are also there for newlines and for doubling. These provisions are there.

SHRI DAYANAND SAHAY: I have asked about the allocation for new lines. What is the budget for new lines?

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : Sir, his question has not been answered. Mr. Dayanand Sahay's question has not been answered.

SHRI BHUPINDER SINGH MANN : What is the need for conversion ?

SHRI MENTAY PADMANABHAM : The question is about conversion.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 6 हजार किलोमीटर का लक्ष्य पूरे भारतवर्ष में रखा गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश का कितना किलोमीटर का लक्ष्य है और इसमें किन-किन परियोजनाओं पर काम चल रहा है और वे कब तक पूरी करेंगे ? साथ ही एक विशेष रूप से मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बुढ़वल से सीतापुर के बीच में एक छोटी लाइन का मार्ग था जिसको करीब 6 महीने से बनाया जा रहा है, उसके बीच में कोई भी सड़क मार्ग का कोई सम्पर्क नहीं है और 6 महीने से वहां के बीच में लोगों को तकलीफ है, तो इस बुढ़वल से सीतापुर के मार्ग को आप कब तक पूरा कराने में सक्षम हैं ?

SHRI K. C. LENKA: Sir, in U. P., 2,694.34 kms. are M. G. lines. Out of this, in the Eighth Five-Year Plan, we have programmed to convert 929 kms. About the particular line, I have no information.

SHRI N. E. BALARAM : Sir, recently, the Railway Minister, in a statement, in Bangalore, said that he was going to increase the total length of metre gauge from 6,000 to 10,000 kms. as envisaged in the Eighth Five-Year Plan. He has also stated that the Prime Minister has shown some anxiety and the Prime Minister has promised to give sufficient funds so that more metre gauge conversion can be taken up. In the light of this, would he consider two metre gauge lines in Kerala to be included in the new scheme ?

SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF: We have already taken up the rail way line for con version in Kerala, so far as the statement and the reference to the Prime Minister are concerned, it is true that the Prime Minister was impressed by the programme. He did say why not take up more lines for conversion, he would try to assist. So, it is in the process. The Prime Minister is

also making efforts. As and when we gel that kind of financial support, we will be able to take up more lines. Right now we are in the process of confining to the track of 6000 kms. which we have already taken up.

SHRI V. NARAYANASAMY. Mr. Chairman, Sir, gauge conversion is actually a good thing not only from the point of view of national development but also from the point of view of giving employment to the rural people of our country. Now the Minister has said that 6000 kms. line has been taken up for conversion into broad gauge, but I have to make one point at the time of allocating broad gauge conversion to various States there is a total discrimination. The reason is the backwardness of the State is not taken care of and an uneven distribution is taking place. I have no quarrel over the issue that Kamataka is being favoured in this regard, but Tamil Nadu has been ignored that is my point. My point is that only one broad gauge line is there and there is a demand from the people of Tamil Nadu and also from my Stete. *'Interruptions).* My hon. friend is also saying about Andhra Pradesh also. From Madurai to Madras the traffic is heavy and conversion is not taken care of. Therefore, I would like to know the criterion that is being followed and whether there is an even distribution or not.

SHRI C. K. JAFFAR SHARIEF : I am sorry, there is a mistaken notion. It is not distributed on the basis of States. The programme is based on one single route. The railway line is not confined to any particular State. We have taken it up from Delhi to Ahmedabad. From there to Miraj and from Miraj to Banga;ore. So, it is based on the route. The idea is to attract the road traffic to the rail traffic. It is based on one single route. That is why you feel somewhere it is more and somewhere it is less. In the gauge conversion programme the Hon share has gone to Rajasthan, not to any other State.

MR. CHAIRMAN : Next Question.

Setting up of Post Graduate Institute of Medical Sciences in Salt Lake, Calcutta

*303. SHRI MOHAMMED AMIN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the proposal to set up a Post Graduate Institute of Medical Sciences in Salt Lake, Calcutta is under active consideration of the Government of India as a memorial of the aminent Historian, ex-Union Minister, diplomat and Governor of West Bengal late Syed Nurul Hassan; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR). (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

श्री मोहम्मद अमीन : सर, ऐसा लगता है कि मंत्री जी ने इस सिलसिले में जो खतो-किताबत हुई है, उसका रिकार्ड देखा नहीं है । टाईम नहीं है, मैं सिर्फ एक लेटर पढ़ देता हूं प्रणव मुखर्जी साहब का जो इस सदन में अब आ रहे हैं । उसका एक पैराग्राफ है—

"Creation of Regional Institutes of Excellence in the field of Medical Sciences by the Central Government will be considered while finalising the Eighth Plan. I assure you that during the formulation of the 8th Plan if the scheme of establishment of Post-Graduate Institute is under Central Health Sector, priority would be accorded to Calcutta so that the long felt need of not only West Bengal but also North-Eastern region and adjoining states are fulfilled."

तो यह प्रणव मुखर्जी साहब, जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टि चेयरमैन थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार को लिखा है । इसके बावजूद मंत्री जी कहते हैं कि यह सवाल पैदा नहीं होता है ।

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Sir, there are requests from various States for the establishment of such type of Institutes in their respective States. The Government has formed a committee to look into the whole problem, and the committee has also given its report. After going through the whole report the Central Government has decided that because establishment of one such Institute requires almost Rs. 200 crores, and the demand being so large from all over the country, it will be very difficult to allocate any money from the Health budget because we have other commitments to fulfil and establishment of such type of Institutes will be a very costly affair.

MR CHAIRMAN: Question Hour is over

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Assistance offered by Israel to India

*304. SHRI PASUMPON THA. KIRUTTINAN:
SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state: